

## असाधार्गा EXTRAORDINARY

দান II—ৰ্গৰ 3—রণ-ৰ্গৰ (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] **नई बिल्ली, मंगलवार, परवरी** 19, 1991/माघ 30, 1912 No. 67] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 1991/MAGHA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

**ग्र**धिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1991

मा. का. ति. 80(म्र).—पासपोर्ट म्रधितियम, 1967 (1967 का 15) (यहां जिसे इसके बाद उक्त ग्रिधितियम कहा गया है) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त मिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बिचार से कि ऐसा करना जन हित में ग्रावस्थक और उचित है, एतद्द्वारा उन व्यक्तियों को, जिन्हें इराक भ्रयवा कुर्वत में 2 ग्रगस्त, 1990 को ग्रथवा उसके बाद प्रत्यावित्त किया गया है श्रथवा किया जा रहा है, उक्त ग्रिधितियम की धारा 6 की उपधारा (2) के

खंड (ज) के उपखंडों के प्रवर्तन से इस शर्त पर छूट प्रदान करती है कि ऐमे प्रत्यावितत व्यक्ति उकत सरकार द्वारा विनिद्धिष्ट रीति से तथा प्रत्येक मामले में प्रत्यावर्तन के रूपम को और उन्हें दी गई वित्तीय महायता यदि कोई हो, को स्थान में रबते हुए उक्त सम्कार द्वारा विनिध्नित राशि का एक बंधपन्न निष्पादित करे।

[मं टी-4111/41/1/90]

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th February, 1991

G.S.R. 80 (E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient in public interest so to do, hereby exempts persons, who have been repatriated or being repatriated from Iraq of Kuwait on or after 2nd August, 1990, from the operation of the provisions of clause (h) of sub-section (2) of section 6 of the said Act subject to the condition that persons so repatriated execute a bond in such manner as may be specified by that Government in an amount as may be determined by that Government in each case, having regard to the cost of repatriation and financial assistance if any, granted to them.

[No. T-4111 | 41 | 1 | 90]

मा. का. नि. 81(म्र)—पामपोर्ट म्रिमिनिमम, 1967 (1967 का 15) (जहां जिसे इसके बाद उक्त म्रिमिनिम कहा गया है) की मारा 22 द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस विचार से कि ऐसा करना जन हित में ग्रावण्यक और उचित है, एतद्द्वारा उन व्यक्तियों को, जिन्हें लाइबेरिया से 1 ग्रगस्त, 1990 को ग्रथवा उसके बाद किन्तु 30 सितम्बर, 1990 से पहले प्रत्याविति किया गया है, उक्त म्रिधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ज) के उपखंडों के प्रवर्तन से इस गर्त पर छूट प्रदान करती है कि ऐसे प्रत्याविति व्यक्ति उक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रत्येक मामले में प्रत्यावर्तन के व्यय को और उन्हें दी गई वित्तीय सहायता यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए उक्त सरकार द्वारा विनिष्वित राणि का एक बंधपत्र निष्पादित करे।

[सं टी.-4111/41/1/90] शशांक, संयुक्त मचिव (सी.पी.बी.) G.S.R. 81 (E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient in public interest so to do, hereby exempts persons, who have been repatriated from Liberia on or after 1st August, 1990 but before 30th September, 1990 from the operation of the provisions of clause (h) of sub-section (2) of section 6 of the said Act subject to the condition that persons so repatriated execute a bond in such manner as may be specified by that Government in an amount as may be determined by that Government in each case, having regard to the cost of repatriation and financial assistance if any, granted to them.

[No. T-4111|41|1|90] SHASHANK, Jt. Secy. (CPV)